

भारतीय शिक्षा प्रणाली पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

Dr. Savita Rajput

Associate Professor, Department of Sociology, DAV (PG) College, Dehradun, Uttarakhand, India

ABSTRACT

देश में कोरोना की आमद 30 जनवरी 2020 में केरल में मिले एक मरीज से हुई और धीरे-धीरे 2020 के खत्म होते-होते कोरोना ने देश में तबाही के कई मंज़र दिखा दिए। इसका व्यापक असर, न केवल उद्योगों और व्यापार पर पड़ा, बल्कि इसका एक बड़ा असर स्कूलों पर, बच्चों की मानसिक स्थिति और उनकी मनोदशा पर भी पड़ा है। लगभग दो वर्ष से महामारी के कारण पूरे भारत के अधिकांश स्कूल बंद चल रहे हैं। बच्चे घरों में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूली छात्रों की सामान्य दिनचर्या, जिसमें केवल क्लासरूम में प्रत्यक्ष पढ़ाई ही नहीं शामिल होती है, बल्कि स्पोर्ट्स, हॉबी विकास, अन्य शिक्षणतर गतिविधियां भी होती हैं, बाधित हो गयी हैं। अचानक हुए इस परिवर्तन ने सभी राज्यों, वर्गों, जाति, लिंग और सभी क्षेत्रों के बच्चों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित किया है। बच्चे एक प्रकार के कैदखाने में कैद हो गए हैं। विशेषकर उन घरों में जो एकल परिवार के हैं और छोटे-छोटे फ्लैटों में पहले ही एक प्रकार के आइसोलेशन में जी रहे हैं। संयुक्त परिवारों और बड़े घरों में तो थोड़ी बहुत, राहत है, पर एकल परिवार और कामकाजी दंपतियों के परिवार के बच्चों पर इस महामारी जन्य कैदखाने का बेहद प्रतिकूल असर पड़ा है। इस सम्बंध में यूनिसेफ द्वारा एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन पर सुजॉय घोष, जो अर्थव्यवस्था और उसके राजनीतिक असर पर अक्सर लिखते रहते हैं, ने इंडियन पोलिटिकल डिबेट वेबसाइट (Sujoy Ghosh's article on the Indian Political Debate website) पर एक गम्भीर लेख लिखा है।

हाल ही में किए गए यूनिसेफ के उक्त अध्ययन के अनुसार स्कूलों के बंद होने से 286 मिलियन छात्र, जिनमें 48 प्रतिशत लड़कियां हैं, और जो पूर्व-प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ती हैं, प्रभावित हुई हैं।

24 मार्च को कोविड-19 रोकथाम के लिए जब देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया, तो, उसके तुरंत बाद राज्यों की सरकारों ने स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन करने का प्रावधान शुरू कर दिया। इसमें एनजीओ, फ़ाउंडेशन और निजी क्षेत्र की तकनीकी शिक्षा कंपनियों को भी भागीदार बनाया गया। इन सब ने मिककर शिक्षा प्रदान करने के लिए संवाद के सभी उपलब्ध माध्यमों का इस्तेमाल शुरू किया। इसमें टीवी, डीटीएच चैनल, रेडियो प्रसारण, व्हाट्सएप और एसएमएस ग्रुप और प्रिंट मीडिया का भी सहारा लिया गया। कई संगठनों ने तो नए अकादमि वर्ष के लिए किताबें भी वितरित कर दीं। स्कूली शिक्षा की तुलना में देखें, तो उच्च शिक्षा का क्षेत्र इस नई चुनौती से निपटने के लिए बहुत ही कम तैयार था।

परिचय

महामारी के दौरान, भारत में, स्कूलों के अचानक बंद हो जाने के कारण, पारंपरिक कक्षा आधारित भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली अब एक अनियोजित ऑनलाइन आधारित शिक्षा प्रणाली के रूप में स्थानांतरित हो गई है। अनियोजित इसलिए कि, न तो हम मानसिक रूप से और न ही तकनीकी रूप से ऑनलाइन शिक्षा की इस अचानक आ पड़ी चुनौती से निपटने के लिये, तैयार थे। अचानक होने वाला यह अप्रत्याशित तकनीकी बदलाव (unexpected technological change) न केवल छात्रों को, डिजिटल रूप से विभाजित कर रहा है, बल्कि उनके सीखने की क्षमता और उनकी समग्र प्रगति (सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल, फिटनेस, आदि) को भी धीमा कर दे रहा है। सामूहिकता

न केवल तरह-तरह से सीखने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि वह तरह-तरह की होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिये बच्चों को मानसिक रूप से तैयार भी करती है। बच्चों पर, उनकी सीखने की क्षमता और विविधता के अलावा, स्कूली शिक्षा की अनुपस्थिति का, बच्चों और किशोरों के समग्र विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ेगा। कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों के बंद होने के कारण (शिक्षा पर covid-19 के प्रभाव) छात्रों के सीखने की क्षमता (learning capacity), पर क्या प्रभाव पड़ा है, का आकलन करने के लिए, यूनिसेफ ने देश के छह राज्यों, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आंकड़े जुटाए और उनका मूल्यांकन और अध्ययन

How to cite this paper: Dr. Savita Rajput "Impact of Covid-19 Pandemic on Indian Education System" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-4, June 2022, pp.490-494, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd50070.pdf



IJTSRD50070

Copyright © 2022 by author(s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)



किया। यह अध्ययन, "कोविड के संदर्भ में स्कूल बंद" प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है।[1,2]

इस मामले के तमाम विशेषज्ञ जैसे कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सहाना मूर्ति का ये मानना है कि आगने सामने की पढ़ाई से अचानक ऑनलाइन माध्यम में स्थानांतरित होने से शिक्षा प्रदान करने का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है. इस ऑनलाइन शिक्षा को आपातकालीन रिमोट टीचिंग कहा जा रहा है. ऑनलाइन एजुकेशन और इमरजेंसी ऑनलाइन रिमोट एजुकेशन में बहुत फर्क है. ऑनलाइन शिक्षा अच्छी तरह से अनुसंधान के बाद अभ्यास में लाई जा रही है. बहुत से देशों में तालीम का ये माध्यम कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पाठ्यक्रम को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके. इसके मुक़ाबले भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में इस ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता काफी कम है. अब अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज आने वाले सेमेस्टर से ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं, तो उन्हें इस रिमोट ऑनलाइन एजुकेशन और नियमित ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी. क्योंकि, अगर देश में कोविड-19 के मरीज़ों की तादाद बढ़ती रही, तो उच्च शिक्षण संस्थानों को भी स्कूलों की ही तरह नियमित ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करनी होगी.

भारत का उच्च शिक्षा का सेक्टर, ऑनलाइन शिक्षा के पाठ्यक्रम को अपनाने में बहुत सुस्त रहा है. इसीलिए अचानक से ऑनलाइन पढ़ाई की ज़रूरत सामने खड़ी हुई, तो ये सेक्टर पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है. 30 जनवरी 2020 तक देश के केवल सात उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे थे जिन्होंने यूजीसी (UGC) की 2018 गाइडलाइन्स के अनुसार ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने की इजाज़त ली हुई थी. कोविड-19 की महामारी फैलने से पहले देश के लगभग 40 हज़ार उच्च शिक्षा संस्थानों में से अधिकतर के पास ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं थी. इसीलिए, जब केंद्र और राज्य सरकारों ने इन संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने छात्रों को पढ़ाई कराने का आमंत्रण दिया, तो ये संस्थान इसके लिए तैयार नहीं थे. ये तो मई महीने के मध्य में जाकर वित्त मंत्री ने एलान किया था कि देश की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के तहत टॉप के 100 शिक्षण संस्थानों को स्वतः ही ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम करने की इजाज़त मिल जाएगी. लेकिन, सरकार के इस क़दम से छात्रों के एक छोटे से वर्ग को ही लाभ होगा.[3,4]

विचार-विमर्श

इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष यह भी है कि, "छात्र स्कूल बंद होने पर स्व-अध्ययन पर समय तो अधिक व्यतीत कर रहे हैं पर सीख कम रहे हैं, जबकि, स्कूल में कम समय बिताते हैं और, अधिक सीखते हैं।" यानी स्कूलों में वे कम समय के बावजूद, अधिक मात्रा में और अधिक तेजी से पाठ्यक्रम सीखते हैं। जबकि घरों में स्व-अध्ययन (self study at home) यानी ऑनलाइन पर अधिक समय देने के बावजूद, अधिक नहीं सीख पा रहे हैं। यह अंतर सामूहिक और एकल अध्ययन के गुणदोष का है। अध्ययन में आये आंकड़ों के अनुसार, 97% छात्र प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे पढ़ाई और सीखने में व्यतीत करते हैं। लेकिन प्रति दिन 3-4 घंटे की पढ़ाई

स्कूल की प्रत्यक्ष पढ़ाई की मात्रा से कम है। साथ ही, स्कूल खुलने के बाद भी, छात्र आमतौर पर होमवर्क, ट्यूशन और अन्य स्व-निर्देशित, चीजों के सीखने की गतिविधियों पर समय बिताते ही हैं। सामूहिकता सीखने की क्षमता, लालसा और उत्कंठा को बढ़ा देती है, जबकि एकल अध्ययन, नीरस और उबाऊ हो जाता है। यह अध्ययन स्कूली बच्चों पर है, न कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति वालों पर। अब अगर हम ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता (Availability of necessary infrastructure and technology for online education) और नेट की पहुंच क्षमता का आकलन करें तो पाएंगे कि हम में से अधिकांश अपने देश में भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक वर्गों में 'डिजिटल हैव नॉट्स' की तरह ही हैं। डिजिटल हैव नॉट्स यानी वे इलाके जो नेटवर्क और अन्य सायबर सुविधाओं में पिछड़े हैं। इस अध्ययन के अनुसार, उपरोक्त छह राज्यों में, 10 प्रतिशत छात्र स्मार्ट फोन, फीचर फोन, टीवी, रेडियो, या लैपटॉप / कंप्यूटर आदि किसी भी उपकरण से वंचित हैं। यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों की व्यथा है, जहां स्कूल और शिक्षक तो हैं पर ऑनलाइन पढ़ाई के लिये आवश्यक उपकरण नहीं हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि, जनता तक प्रौद्योगिकी की पहुंच अभी दूर की बात है।

यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि कई इलाकों में दूरस्थ शिक्षण संसाधनों, ऑनलाइन सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद, सर्वेक्षण किए गए छह राज्यों में 40 प्रतिशत छात्रों ने स्कूलों के बंद होने के बाद से किसी भी प्रकार के दूरस्थ या ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग नहीं किया।

जब ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग न करने वाले छात्रों से पूछा गया कि, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण उपकरणों का उपयोग क्यों नहीं किया, तो 73 प्रतिशत छात्रों ने इसे सीखने की सामग्री या संसाधनों के बारे में जागरूकता की कमी का होना बताया।[5,6]

लॉकडाउन लगने के बस दो दिन बाद ही, यूजीसी ने सरकार के ICT यानी सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीक पर आधारित संसाधनों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पहल की एक लिस्ट जारी की थी. यूजीसी का कहना था कि इसके माध्यम से छात्र, लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में पढ़ाई जारी रख सकते हैं. इसमें स्वयं (SWAYAM) और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे विकल्पों का जिक्र किया गया था. हाल ही में छात्रों को सेकेंड डिग्री की शुरुआत की अनुमति भी दे दी गई है. जिसे वो अपने नियमित डिग्री कोर्स के साथ साथ ऑनलाइन या ओपन और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, ये शानदार प्रयत्न हैं, जिनसे छात्रों को कोविड-19 की महामारी के बाद भी बहुत लाभ होगा. लेकिन ऑनलाइन उच्च शिक्षा की बात करें तो अभी भी ये बहुत देर से और कुछ ही छात्रों के लाभ के लिए उठाए गए क़दम हैं. और अधिक ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने की राह में जो प्रमुख चुनौतियां हैं, उनमें से एक ये है कि पढ़ाने वाले अधिकतर फैकल्टी के सदस्यों को इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है. और इसीलिए वो ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के लिए तैयार नहीं हैं. पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्स की योजना बनाने और इसकी तैयारी के लिए छह से नौ महीने लग सकते हैं. इन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ हफ्तों में ही तैयार नहीं किया जा सकता. ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने की पहल करने वाले संस्थानों और फैकल्टी के सदस्यों

को अपने सहकर्मियों को इसे अपनाने में काफ़ी मदद करने की ज़रूरत होगी। फिर चाहे वो अपने ही संस्थान हों या शिक्षण समुदाय के अन्य सदस्य हों। ओआरएफ (ORF) द्वारा इस विषय में आयोजित वेबिनार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नई शिक्षा नीति की ओएसडी (OSD) डॉक्टर शकीला शम्सु ने इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया था। आमतौर पर फैकल्टी के सदस्य, अपने कोर्स के दूसरे या तीसरे सत्र में जाकर ऑनलाइन शिक्षा देने को लेकर सहज हो पाते हैं। ऐसे में उन्हें इसकी शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें तकनीक के महारथी टीचिंग सहायकों के माध्यम से मदद दी जानी चाहिए। अभी तक भारत ने इस विकल्प को नहीं अपनाया है। जबकि विदेशों के विश्वविद्यालयों में टीचिंग असिस्टेंट (TAs) का उपयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। ये शिक्षण सहयोगी, छात्रों के लिए चैट रूम और सहकर्मियों से सीखने के सत्र भी आयोजित करते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करने में बहुत लाभप्रद होते हैं।

अभी भी ऑनलाइन शिक्षा को बहुत से फैकल्टी सदस्य आमने सामने की तालीम के मुकाबले कमतर मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कैम्पस की पढ़ाई को पूरी तरह ऑनलाइन से स्थानांतरित कर पाना संभव नहीं है। खासतौर से अगर किसी को दोनों में से एक को चुनने का विकल्प दिया जाए तो। लेकिन, अगर ऑनलाइन कोर्स को निर्देश के उच्च माध्यमों जैसे कि ऑडियो-वीडियो क्लिप के आधार पर तैयार किया जाए, तो उससे ऑनलाइन शिक्षा को बहुत उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे नियमित यूनिवर्सिटी शिक्षा को काफ़ी मदद मिलेगी। ये बात कोर्सरा, एडेक्स और अन्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से साबित की है। नए सत्र की शुरुआत में देरी से उच्च शिक्षण संस्थानों और फैकल्टी को ये अवसर मिला है कि वो उच्च गुणवत्ता के ऑनलाइन कोर्स तैयार कर लें। [7,8]

परिणाम

उपरोक्त अध्ययन, दो महत्वपूर्ण समस्याओं का संकेत देते हैं। एक, ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों का सामर्थ्य (the potential of online learning resources) और दूसरे इनके प्रति, जागरूकता। माता-पिता या अभिभावकों के एक समूह के लिए, एक मुख्य बाधा डिवाइस और इंटरनेट (डेटा) पाने की क्षमता और सामर्थ्य है, यानी वे ऑनलाइन पढ़ाना तो चाहते हैं पर उनमें इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए ज़रूरी उपकरण (Essential tools for online education) खरीद सकें। वहीं दूसरी ओर, एक अन्य समूह, ऐसे माता-पिता और अभिभावकों का है, जो अपने बच्चों के लिए उपकरण और इंटरनेट दोनों का खर्च, आसानी से वहन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण उपकरण और प्रक्रिया के उपयोग के बारे में, उनमें पर्याप्त जागरूकता का अभाव है। यूनिसेफ ने इस अध्ययन में, ऑनलाइन स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता को अपने अध्ययन का एक प्रमुख बिंदु रखा है।

यूनिसेफ के इस अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार, "माता-पिता और शिक्षक दोनों महसूस करते हैं कि छात्र स्कूलों की तुलना में दूरस्थ (ऑनलाइन अध्ययन के लिए, दूरस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है) शिक्षा के माध्यम से कम सीखते हैं। 5 से 13 वर्ष की आयु के छात्रों के 76 प्रतिशत और 14 से 18 वर्ष की आयु के 80 प्रतिशत, किशोरों के बारे में इस अध्ययन की रिपोर्ट है कि छात्र

स्कूलों में जितना, सीखते हैं, उसकी तुलना में ऑनलाइन शिक्षा में वे कम सीख रहे हैं।

अध्ययन के अनुसार, 67 प्रतिशत शिक्षक यह मानते हैं कि यदि स्कूल खुले रहते तो जितना छात्र स्कूलों में जाकर पढ़ते सीखते हैं, उसकी तुलना में छात्र अपनी समग्र सीखने की क्षमता में पिछड़ रहे हैं, खासकर प्राथमिक स्कूलों के छात्र इसमें अधिक नुकसान में हैं। [9,10]

सीखने की क्षमता में कमी के अतिरिक्त, स्कूल बंद होने के कारण, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर (Impact on mental health of students due to school closure) पड़ा है। जैसे-जैसे छात्र अपने घरों में, महामारी जन्य आइसोलेशन में कैद होते गए, वे अपने मित्रों और शिक्षकों से दूर होते गए। साथ ही महामारी में आने वाली बुरी खबरों का असर जो घर के बड़ों पर पड़ा, उनके तनाव से भी बच्चों और किशोरों के मन मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

माता-पिता की नौकरियों पर असर पड़ा, कुछ महामारी के ग्रास बन गए तो, इसका असर पड़ा और घर में लगातार महामारी जन्य नकारात्मकता ने बच्चों को मानसिक रूप से रुग्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर के जबरिया थोपे गए एकांत और हमउम्र मित्रों के अभाव के कारण उपजी संवादहीनता ने बच्चों के सीखने की क्षमता और स्वाभाविक जिज्ञासु भाव को बहुत अधिक प्रभावित किया है।

अध्ययन से यह पता चलता है कि, 5 से 13 वर्ष की आयु के एक तिहाई छात्रों और लगभग आधे किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर खराब असर या बहुत ही खराब असर पड़ा है।

अध्ययन के दौरान परिवारों से साक्षात्कार भी लिये गये। उनके अनुसार, "सामाजिक अलगाव, सीखने में व्यवधान और परिवार की वित्तीय असुरक्षा खराब मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख कारण हैं।" [11,12]

देश में, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम (मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में), मिड डे मील (एमडीएम) के कई लाभ (benefits of mid day meal) हैं जैसे कि कक्षा में भूख से बचना, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना और सबसे प्रमुख, कुपोषण को दूर करना है। अब, देश भर में स्कूल बंद होने के कारण, 'स्कूल फीडिंग कार्यक्रम अब योजना (एमडीएम पोर्टल) के तहत नामांकित 115.9 मिलियन बच्चों को बहुत ज़रूरी मुफ्त दोपहर का भोजन प्रदान नहीं कर सका।' इसलिए, सीखने के अलावा, स्कूली शिक्षा की अनुपस्थिति का भी बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

कोरोना की स्थिति तुलनात्मक रूप से थोड़ी बेहतर हुई तो माता-पिता और सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में सोचना शुरू कर ही दिया था कि कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के मामले बढ़ने लगे। बच्चों का टीकाकरण अभी नहीं हुआ है और संक्रमण का खतरा उठाना भी उचित नहीं है तो स्कूलों को खोलने की योजना पर सरकारें जो सोच रही थीं, उन पर फिर ग्रहण लग गया।

यूनिसेफ की रिपोर्ट ने एक और तथ्य की ओर इशारा किया है कि, 'लगभग 8 प्रतिशत छात्र स्कूल खुलने के बाद, अगले तीन महीनों में या उसके बाद स्कूल नहीं लौट सकेंगे। उनमें से

अधिकांश (60%) स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण स्कूल नहीं लौट पाएंगे।

इस त्वरित मूल्यांकन रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया कि 'स्कूल बंद होने के एक बड़े झटके के रूप में, कुछ बच्चे वापस लौटने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। वे पूरी तरह से स्कूल छोड़ सकते हैं।

10 प्रतिशत परिवारों का कहना है कि वे बच्चों को वापस स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते जबकि 6 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें जीने योग्य आय अर्जित करने के लिए, अपने बच्चों की मदद की आवश्यकता है।' जैसा कि आईआईटी बंगलोर के प्रोफेसर वी श्रीधर ने ओआरएफ (ORF) के वेबिनार में कहा था, ऑनलाइन कोर्स के विस्तार के पीछे एक आर्थिक तर्क भी है. ऑनलाइन शिक्षा के तमाम प्लेटफॉर्म की कामयाबी इसकी मिसाल है. ऑनलाइन कोर्स बहुत कम खर्चीले होते हैं. और इन प्लेटफॉर्म पर बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं. भारत के लिए अच्छा ये होगा कि वो इस महामारी से मिले अवसर का लाभ उठाकर ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाए. ताकि देश के शिक्षण संस्थान इस आपदा द्वारा दिए गए लंबी अवधि के अवसर को पहचान का उसका लाभ उठाएं. हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने ऑनलाइन शिक्षा के खुद से बढ़ावा देने वाले कोर्स लॉन्च किए हैं, जिनसे कॉलेज के शिक्षक लाभ उठा सकते हैं. ऐसे और अधिक संसाधन तैयार करने आवश्यक हैं. और इन्हें ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार के लिए अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए. खासतौर से भारतीय भाषाओं में. महामारी की इमरजेंसी के दौरान दूरस्थ शिक्षा यानी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर सारी परिचर्चाएं इस बुनियाद पर आधारित हैं कि सभी छात्रों के पास इंटरनेट सेवा है. और सभी के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उपकरण यानी लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद हैं. जिसकी मदद से वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं. पर दुर्भाग्य की बात ये है कि ये बात स्कूल के स्तर पर भी गलत है और उच्च शिक्षा के स्तर पर भी. स्कूलों में जहां स्थानीय समुदायों के ही छात्र आमतौर पर पढ़ाई करते हैं. वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र दूर दराज़ से भी आते हैं. ये अलग अलग राज्यों के छात्र भी हो सकते हैं और ग्रामीण इलाकों के रहने वाले भी हो सकते हैं. ऐसे में, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर अगर इसी आकलन पर कि सभी छात्रों के पास इसके संसाधन होंगे, तो इसका बुरा प्रभाव लगभग सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर पड़ेगा. क्योंकि ज्यादातर छात्र, जो लॉकडाउन के बाद अपने घर लौट गए, उनके पास इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा नहीं थी. नेशनल सैपल सर्वे के शिक्षा से जुड़े 75वें चरण के आंकड़े बताते हैं कि देश में केवल 24 प्रतिशत घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है. इनमें से 42 फ्रीसद शहरी क्षेत्रों में हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के केवल 15 प्रतिशत घरों में इंटरनेट की सुविधा है. वहीं देश के केवल 11 प्रतिशत घरों में अपने कंप्यूटर हैं. (23 प्रतिशत शहरी घरों में कंप्यूटर हैं. तो गांवों में केवल 4.4 प्रतिशत घरों में अपने कंप्यूटर हैं. इसमें स्मार्टफोन को शामिल नहीं किया गया है.) आईएएमएआई (IAMAI) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय लगभग 50 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं. इनमें से 43.3 करोड़ यूज़र 12 साल की आयु से ज्यादा के हैं. और 65 प्रतिशत पुरुष हैं.

ग्रामीण और शहरी, पुरुषों और महिलाओं के बीच के इस डिजिटल अंतर को अन्य बड़े विश्वविद्यालयों सर्वे भी सही बताते हैं. जैसे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के अनुसार केवल 37 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि वो ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं. वहीं 90 प्रतिशत छात्रों ने क्लास में लेक्चर लेने को तरज़ीह देने की बात कही. यहां तक कि देश के बड़े तकनीकी संस्थानों यानी की आईआईटी के दस प्रतिशत या इससे भी अधिक छात्रों ने कहा कि वो स्टडी मैटीरियल को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं. या वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं. छात्रों ने इसकी वजह कभी तो कनेक्टिविटी और कभी अपर्याप्त डेटा प्लान बताई.[13]

निष्कर्ष

पश्चिम बंगाल में एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया है कि महामारी के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों के बाल श्रम में 105% की वृद्धि हुई है। महामारी के दौरान 'सेव द चिल्ड्रन' द्वारा इसी तरह के एक सर्वेक्षण में शामिल 62 प्रतिशत परिवारों, जिसमें क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में 67 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत हैं, के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है।

महामारी का व्यापक असर देश की आर्थिकी पर पड़ा है। 2016 में हुई नोटबन्दी के कारण 31 मार्च 2020 तक देश की जीडीपी में 2 प्रतिशत गिरावट आ चुकी थी और फिर जब महामारी का दौर आया तो, लम्बे समय तक चलने वाले रुक रुक के लॉक डाउन, कामगारों के व्यापक और देशव्यापी विस्थापन ने, देश की बेरोज़गारी दर को और बढ़ा दिया जिससे मंदी जैसे हालात पैदा हो गये। इसका सीधा असर, लोगों की जीवन शैली पर पड़ा और बच्चों की शिक्षा इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई। लोगों के पास, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिये धन की कमी हुई तो शिक्षा जो सरकार की प्राथमिकता में तो वैसे भी नहीं है, अब इन विपन्न परिवारों में भी प्राथमिकता से धीरे-धीरे बाहर होने लगी। इसका प्रभाव आगे चल कर उन गरीब परिवारों पर अधिक पड़ेगा, जिन्हें बजट की कमी का सामना बराबर करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, गरीब होते परिवारों के बच्चे स्कूल छोड़ देंगे और अपने माता-पिता की कमाई में मदद करने के लिए आर्थिक गतिविधियों में लग जाएंगे। यह स्पष्ट है कि बच्चे जितने अधिक समय तक स्कूल से बाहर रहते हैं, वे उतने ही कमजोर होते जाते हैं और उनके स्कूल लौटने की संभावना भी कम होती जाती है।

सरकार को शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को गम्भीरता से लेना होगा। देश में सरकारी स्कूली शिक्षा की बात करें तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। निजी स्कूल ज़रूर बहुत हैं और अब भी खुल रहे हैं, पर वे दिन पर दिन महंगे भी होते जा रहे हैं और तरह-तरह के शुल्कों के कारण, एक सामान्य वेतनभोगी या निम्न मध्यवर्ग की पहुंच के बाहर भी हैं। ऐसे स्कूलों के फीस ढांचे पर सरकार का या तो कोई नियंत्रण नहीं है या सरकार जानबूझकर उन्हें नियंत्रित करना ही नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में पढ़ाई की असल नींव जो स्कूली शिक्षा में पड़ती है, वह नहीं बन पा रही है।[14]

महामारी एक अस्थायी समस्या है। टीकाकरण और अन्य इलाज की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। स्थिति सामान्य होगी ही और स्कूल भी खुलेंगे। पर शिक्षा, कम से कम स्कूली शिक्षा तो

सर्वसुलभ हो, यह देश और समाज की बेहतरी के लिये अनिवार्य है।

ऑनलाइन शिक्षा, एक मज़बूरी भरा विकल्प है जो इस महामारी जन्य आफ़तकाल में स्कूल से आभासी रूप से जोड़े रखने का एक उपक्रम भर है। असल शिक्षा तो स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों में सामूहिक क्लास रूम में मिलती है न कि मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप के स्क्रीन पर।

रैंकिंग एजेंसी क्वाक़ारेली सायमंड्स (QS) के एक ताज़ा सर्वे को उनके क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने ORF के वेबिनार में प्रस्तुत किया था। इस सर्वे में दिखाया गया था कि इसमें शामिल 7500 से अधिक छात्रों में से 72.6 प्रतिशत, इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए मोबाइल फ़ोन हॉट स्पॉट का इस्तेमाल करते हैं। यूनेस्को इंटरनेट सुविधा के इस माध्यम को ख़राब तकनीक का कहता है। केवल 15.87 प्रतिशत छात्रों के पास ब्रॉडबैंड की सुविधा थी। मगर, इन छात्रों ने बताया कि उनके ब्रॉडबैंड में भी कनेक्टिविटी की समस्याएं आती थीं। कभी बिजली नहीं रहती थी और कभी सिग्नल नहीं होता था। और जो छात्र मोबाइल हॉट स्पॉट का इस्तेमाल इंटरनेट के लिए कर रहे थे, उनमें से लगभग 97 प्रतिशत को ख़राब कनेक्टिविटी या सिग्नल न मिलने की चुनौतियां झेलनी पड़ रही थीं। अब अगर हम इन आंकड़ों को इस बात से जोड़ कर देखें कि केवल 30 प्रतिशत भारतीय आबादी के पास ही स्मार्टफ़ोन हैं, तो आपको पता चलेगा कि देश की कुल आबादी का बेहद छोटा सा हिस्सा स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करता है। सबसे अच्छी पहुंच वाली तकनीक यानी टीवी चैनल का इस्तेमाल शिक्षा के लिए करना भी एक समाधान नहीं है। क्योंकि, देश के केवल 67 प्रतिशत घरों में ही टीवी है।

आज स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, टीवी वगैरह को आपस में साझा करने के विकल्प भी आजमाए जा रहे हैं। लेकिन, अगर एक छात्र भी ऑनलाइन शिक्षा के दायरे से बाहर रह जाता है, तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। ऑनलाइन शिक्षा के लंबी अवधि के समाधान के लिए राज्यों और केंद्र की सरकारों को चाहिए कि वो सभी शिक्षण संस्थानों को अच्छी ब्रॉडबैंड सेवा और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर उपलब्ध कराएं। देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली योजना भारत नेट 2011 से चल रही है। लेकिन, आख़िरी छोर तक इंटरनेट की सेवा न पहुंच पाने से ये योजना भी अधर में ही लटकी है। जब भी ये योजना पूरी तरह कार्यान्वित होती है, और इसे प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, तब ये ग्रामीण समुदायों और छात्रों को अच्छी ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ सकेगी। तब इसका इस्तेमाल न सिर्फ़ शिक्षा के लिए हो सकेगा। बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और रोज़गार के अन्य माध्यमों में भी ये लोगों की मदद कर सकेगी।

तब तक उच्च शिक्षा के सभी फैकल्टी सदस्यों को उपलब्ध संसाधनों से भी काम चलाना होगा। ताकि वो अपने सभी छात्रों से लगातार संपर्क में रहें और अपनी चतुराई से इन छात्रों को इस कोरोना काल में पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहें। ये आपदा एक अवसर बन सकती है, अगर हम उच्च शिक्षा देने के लिए नई परिकल्पनाओं पर काम कर सकें। शिक्षा को लेकर पारंपरिक सोच को परे हटाकर अध्ययन, अध्यापन और

समीक्षा के नए तरीक़े अपनाएं। हमेशा के लिए नहीं, तो कम से कम इस अवधि में तो ऐसा हो ही सकता है।[15]

संदर्भ

- [1] "लॉकडाउन में राहत के बाद भी ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही अर्थव्यवस्था? जानें". जनसत्ता. 13 जुलाई 2020. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
- [2] "कोरोना के सामने घुटनों पर आई दुनिया की अर्थव्यवस्था". आज तक. मूल से 29 जून 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
- [3] "आईएमएफ ने कहा, कोविड-19 का लगातार फैलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा". हिन्दुस्तान लाइव. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
- [4] "कोरोना वायरस के कारण भारत में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियां". ORF. मूल से 10 मई 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
- [5] Ward, Alex (2020-03-24). "India's coronavirus lockdown and its looming crisis, explained". Vox (अंग्रेज़ी में). मूल से 28 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2020-03-25.
- [6] Bureau, Our. "PM Modi calls for 'Janata curfew' on March 22 from 7 AM-9 PM". @businessline (अंग्रेज़ी में). मूल से 20 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 March 2020.
- [7] "India's 1.3bn population told to stay at home". BBC News (अंग्रेज़ी में). 2020-03-25. मूल से 31 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 March 2020.
- [8] "पूरा देश लॉकडाउन की ओर, 31 मार्च से पहले फिर हो सकता है जनता कर्फ्यू का आह्वान". अमर उजाला. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
- [9] "कोरोना का प्रभाव, 2020 में 4.5 फीसदी GDP का अनुमान: सरकार". अमर उजाला. मूल से 9 जुलाई 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
- [10] "At -23.9%, GDP Contracts For First Time In Over Four Decades". NDTV.com.
- [11] "Coronavirus Update (Live): 25,592,318 Cases and 853,437 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic - Worldometer". www.worldometers.info (अंग्रेज़ी में).
- [12] "At -23.9%, GDP Contracts For First Time In Over Four Decades". NDTV.com.
- [13] अहमद, जुबैर (1 मई 2020). "कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था स्वदेशी की तरफ़ जाएगी?". BBC News हिंदी. मूल से 27 जून 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 जुलाई 2020.
- [14] शर्मा, अभय. "कैसे इस बुरे वक्त में हमारे गांव देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा रहे हैं". सत्याग्रह. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
- [15] "कोविड-19: भारत में 'लॉकडाउन' से प्रवासी कामगारों पर भारी मार". संयुक्त राष्ट्र समाचार. 2 अप्रैल 2020.